एम. एम. पुंछी और ए. एल. बहरी, जे.जे. के समक्ष।

रमेश चंदर जैन-याचिकाकर्ता।

बनाम

उप आयुक्त। गुड़गांव और न्य,

-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 11043।

17 गस्त 1989.

भारत का संविधान 1950- नुच्छेद 226 और 227-लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस-उत्तर में लाइसेंसधारी व्यक्तिगत सुनवाई का दावा करता है- ऐसी कोई सुनवाई नहीं दी गई- ऐसे आदेश की वैधता।

माना गया कि हमारा मानना है कि न्याय का गर्भपात हुआ है। लिखित दलीलों के लावा, मौखिक दलीलें हमारी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। र्धन्यायिक स्तर पर भी यही आवश्यक है। यह कोई नुष्ठान नहीं है जिसे कागज़ी वसर देकर किया गया मान लिया जाए। चूँकि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया था, जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इसकी पेक्षा कम ही थी।

आपूर्ति नियंत्रक को याचिकाकर्ता को सुनवाई की तारीख सूचित करनी थी ताकि वह लिखित रूप में जो कहा गया था उसे प्रमाणित और समझा सके। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त □ पीलीय उपाय भी मूल दोष से ग्रस्त है क्योंकि इसने □ नुदान के मामले में जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक के विचारों का समर्थन किया था: व्यक्तिगत सुनवाई।

(पैरा 3).

भारत के संविधान के □ नुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि-.-

(i) उस मामले का रिकॉर्ड, जिसे उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 से बुलाया था और उसके □ वलोकन के बाद उन्होंने एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश पारित किया, जिसमें आदेश □ नुलग्नक पी-3 और पी-5 को रद्द कर दिया गया।

(ii) प्रतिवादियों को निर्देश जारी किया जाए कि याचिकाकर्ता का ग्राम खेड़की मजार का खाद्य वितरण लाइसेंस बहाल किया जाए।

(iii) उत्तरदाताओं की सेवा के लिए रिट याचिका की □ ग्रिम प्रतियां दाखिल करने की छूट दी जाए।

(iv) कृपया □ नुलग्नक पी-1 से पी-5 पत्रिका की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की छूट दी जाए।

(v) रिट याचिका की लागत की □ नुमति दी जाए।

आगे यह प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, रिट याचिका के निर्णय तक विवादित आदेश नुलग्नक पी-3 और पी-5 पत्रिका के संचालन पर रोक लगाई जाए।

सिविल विविध. नहीं। 1988 का 15905.

सीपीसी की धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान। आदेश नुलग्नक पी/3 3 और पी/5 के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की वकील नीना बंसल के साथ वरिष्ठ धिवक्ता शोक ग्रवाल।

5. एस बलावत. डी.ए.जी. हरियाणा राज्य के लिए.

निर्णय

(1) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने इस स्तर पर इस याचिका का निपटारा करना बेहतर समझा।

(2) याचिकाकर्ता हरियाणा के गुड़गांव जिले के तीन गांवों में खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण के लिए एक लाइसेंस प्राप्त डिपो धारक था। कुछ गबन के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था,

हमेश चंदर जैन बनाम उपायुक्त, गुड़गांव और न्य (एम.एम. पुंछी, जे.)

दिनांक 22 □ प्रैल, 1988, □ नुलग्नक पी.1, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, गुड़गांव द्वारा उनसे कारण बताने के लिए कहा गया कि क्यों न उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। साथ ही उनसे पूछा गया कि वह निर्धारित □ वधि के भीतर उक्त □ धिकारी को व्यक्तिगत रूप से मामले को समझाकर कारण बता सकते हैं। याचिकाकर्ता ने एक लंबा जवाब, □ नुलग्नक पी.2 प्रस्तुत करके कारण बताओ नोटिस के आधार का खंडन किया। चूंकि उन्हें सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख नहीं दी गई थी, इसलिए उनके लिए यह □ नुमान लगाना गलत नहीं था कि उन्हें तारीख की सूचना मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कहा था। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने सोचा कि यदि कारण बताओ नोटिस दिया गया है और याचिकाकर्ता को आकर □ पना मामला समझाने का खुला □ वसर दिया गया है तो यह कानून का पर्याप्त □ नुपालन है। उन्होंने तदनुसार □ पना लाइसेंस रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता की □ पील को गुड़गांव के उपायुक्त ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि कोई व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक नहीं थी और इसके □ लावा याचिकाकर्ता तीन गांवों में लाइसेंस का हकदार नहीं था, जो □ पने आप में रद्दीकरण को उचित ठहराता था।

(3) आक्षेपित आदेशों, □ नुलग्नक पी.3 और पी.5 को देखने के बाद, हमारा मानना है कि न्याय का गर्भपात हुआ है। लिखित दलीलों के □ लावा, मौखिक दलीलें हमारी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। □ र्ध-न्यायिक स्तर पर भी यही आवश्यक है। यह कोई □ नुष्ठान नहीं है जिसे कागजी □ वसर देकर किया गया मान लिया जाए। चूंकि याचिकाकर्ता ने कारण

बताओ नोटिस के खिलाफ एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया था, इसलिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक से कम से कम यह उम्मीद की गई थी कि वह याचिकाकर्ता को सुनवाई की तारीख की सूचना देगा ताकि वह लिखित में जो कहा गया था उसे प्रमाणित और समझा सके। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया पीलीय उपाय भी मूल दोष से ग्रस्त है क्योंकि इसने व्यक्तिगत सुनवाई की नुमति के मामले में जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक के विचारों का समर्थन किया था।

(4) इन कारणों से, हम रिट याचिका की नुमति देते हैं, "आदेशों, नुलग्नक पी.3 और पी.5 को रद्द करें, और याचिकाकर्ता को सुनवाई की नुमति देने के लिए मामले को जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक को वापस भेज दें। वह ब याचिकाकर्ता को इस उद्देश्य के लिए एक तारीख जारी करेगा जब वह उसे सुविधाजनक रूप से सुन सके। कोई लागत नहीं.

*एस.सी.के.

 स्वीकरण : स्थानीय भाषा में नुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह पनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का ंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा